अमन चौधरी से पहले, जे. के समक्ष

शेर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सी. आर. एम.-एम. संख्या 2022 का 37884

26 अगस्त, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 438-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. एस. 406, 420, 468, 471-याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग की-शिकायतकर्ता के स्थान पर सह-अभियुक्त सतपाल का स्वामित्व दिखाने के लिए सरकार के जाली राजस्व रिकॉर्ड का आरोप, बैंक से ऋण प्राप्त करना-माना कि यह एक ऐसी संपत्ति पर बैंक का प्रभार बनाने का मामला है जिसका न तो याचिकाकर्ता और न ही सह-अभियुक्त सतपाल मालिक थे-अदालत अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है-याचिका खारिज कर दी गई।

मान लिया गया कि मामले में आरोप बैंक से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता के स्थान पर सह-अभियुक्त सतपाल के स्वामित्व को दिखाने के लिए सरकार के राजस्व रिकॉर्ड को जाली बनाने के हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त सतपाल की सहायता की थी। (पैरा 7)

आगे अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने कथित रूप से शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली उक्त संपत्ति पर बैंक का प्रभार बनाने के लिए गवाही दी। इसलिए, यह केवल विलेख आदि के पंजीकरण के लिए अधिकारियों के समक्ष निष्पादक की पहचान का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी संपत्ति पर बैंक का प्रभार बनाने का मामला है, जिसके न तो सह-अभियुक्त सतपाल थे और न ही याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता पर की जा रही धोखाधड़ी स्पष्ट प्रतीत होती है कि सह-अभियुक्त सतपाल द्वारा भुगतान न आदेश पर ऋण राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा उसकी जमीन भी बेची जा सकती है।

(पैरा 7)

आगे कहा कि यह न्यायालय याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता की ओर से पंकज बाली, अधिवक्ता

गौरव बंसल, ए. ए. जी, हरियाणा।

प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह

अमन चौधरी, जे.

(1) खंड 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वर्तमान याचिका प्राथमिकी को अग्रिम जमानत देने के लिए दायर की गई है, जो कि खंड 406,420,468,471 भा.दं.सं. सी. के तहत पुलिस स्टेशन असंध, जिला करनाल में दर्ज की गई है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिया गया है, लेकिन वह सह-आरोपी सतपाल द्वारा बैंक से उठाए गए कथित ऋण का लाभार्थी नहीं है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि उसने एक सह-ग्रामीण होने के नाते केवल उक्त सह-अभियुक्त की पहचान की थी।वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है, सतपाल मुख्य आरोपी है।

(3) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील अग्रिम जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हैं। उन्होंने ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता की संपत्ति पर आरोप लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता की भूमि का जाली राजस्व रिकॉर्ड है।इसे 'ए' के रूप में “चिह्नित ए” किया गया है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि जांच एजेंसी ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ पर भरोसा करके सह-आरोपी सतपाल और याचिकाकर्ता के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

(4) शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड को जाली बनाकर, याचिकाकर्ता के साथ-साथ सह-आरोपी सतपाल और प्रमोद ने शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि को गिरवी रखने की साजिश रची थी। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यदि सह-अभियुक्त सतपाल और बैंक के बीच समझौते के माध्यम से उक्त ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता की भूमि बेची जाएगी।वास्तव में, वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मुख्य साजिशकर्ता है।

(5) राज्य के विद्वान अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत को अस्वीकार करने के आदेश में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता ने नकली और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की थी।वे दोनों आगे कहते हैं कि वास्तव में वह सह-अभियुक्त सतपाल के साथ नकली और जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त करने के लिए पूरे लेनदेन का एक अभिन्न हिस्सा था क्योंकि वह एक सह-ग्रामीण है और उसे पता था कि भूमि सह-अभियुक्त सतपाल की नहीं है।उपरोक्त तथ्य को पूरी तरह से जानते हुए, उन्होंने ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक को प्रस्तुत आवेदन को सत्यापित किया था, जिसके तहत बैंक के पक्ष में शुल्क बंधककर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा के अनुसार बनाया गया था, ऐसा करके राजस्व शिकायतकर्ता की भूमि के संबंध में अभिलेख उनके द्वारा जाली बनाया गया था और सह-अभियुक्त सतपाल के स्वामित्व में दिखाया गया था, परिणामस्वरूप, उक्त भूमि पर आरोप लगाया गया था, जो वास्तव में शिकायतकर्ता के स्वामित्व में थी।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने खंडन में प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश में, यह केवल उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता ने केवल सह-अभियुक्त सतपाल को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान की थी, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उसने केवल सह-अभियुक्त सतपाल की पहचान की थी।

(7) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।मामले में आरोप बैंक से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता के स्थान पर सह-अभियुक्त सतपाल के स्वामित्व को दिखाने के लिए सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में जालसाजी करने के हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त सतपाल की सहायता की, जैसा कि दस्तावेज़ चिन्हित 'ए' से स्पष्ट है कि यह खंड 4 (1) के तहत घोषणा के आधार पर कृषि भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में शुल्क/उत्परिवर्तन दर्ज करने के लिए एक आवेदन है। यह वास्तव में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक रूप है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कथित रूप से शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली उक्त संपत्ति पर बैंक का प्रभार बनाने के लिए गवाही दी है। इसलिए, यह केवल विलेख आदि के पंजीकरण के लिए अधिकारियों के समक्ष निष्पादक की पहचान का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी संपत्ति पर बैंक का प्रभार बनाने का मामला है, जिसके न तो सह-अभियुक्त सतपाल थे और न ही याचिकाकर्ता मालिक थे, ना ही शिकायतकर्ता के साथ की गई धोखाधड़ी स्पष्ट प्रतीत होती है कि सह-अभियुक्त सतपाल द्वारा चुकाया नहीं जाने पर ऋण राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा उसकी जमीन भी बेची जा सकती है।

(8) उपरोक्त टिप्पणियों और राज्य के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को देखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(9) हालाँकि, जाँच एजेंसी, यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियों से अप्रभावित, अपनी जाँच जारी रख सकती है, जो केवल वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से की गई हैं और किसी भी तरह से, मामले के गुण-दोष पर एक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जा सकती हैं।

दिव्या गुर्ने

रजनीश सिंगला

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय क अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।